>

Title : Need to review the rate of honorarium to cooks preparing mid-day meal in the country.

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को पोषण आहार दिया जाना है। यह योजना 75 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। महंगाई और अन्य कारणों से खाद्यान्न सामग्री की दरों पर समय-समय पर उक्त योजना की राशि में वृद्धि होती रहती है, परन्तु रूचिकर पौष्टिक मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोइयों को मात्र एक हजार रुपए ही मानदेय दिया जाता है, जबकि उक्त योजना के क्रियान्वयन में रसोइयों की भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की मनरेगा योजना में भी प्रतिदिन मजदूरी 122 रुपए है, जबकि मध्यान्ह भोजन के रसोइए को लगभग 33 रुपए प्रतिदिन ही दिया जाता है, यह कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। देश के प्रत्येक जिले में जिला कलैक्टर के यहां कुशल/अकुशल दैनिक वेतन भोगी एवं अन्य मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी की दर निर्धारित है, जो कि उक्त राज्य के श्रम विभाग के मापदंडों के अनुरूप होती है। लेकिन वर्तमान में मध्यान्ह भोजन के रसोइयों के नाम से जिला कलेक्टर के पास कोई गाइडलाईन नहीं है।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि प्रत्येक राज्य सरकारों को इस संबंध में निर्देश जारी किए जाएं कि मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोईयों के मानदेय का भुगतान कम से कम उस जिले में प्रचलित कलैक्टर दर के अनुरूप किया जाए।

MR. CHAIRMAN : Shri Mohinder Kumar Kaypee.

It is a State subject, you can just make a mention.